PK टाइम्स

# लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 319 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | गुरुवार 04 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

# बजट घोषणाओं को रफ्तार : प्रदेश के 29 जिलों के ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों का बदलेगा भूगोल

## सीएम का बड़ा फैसला, 882.54 करोड़ की 137 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

### पीडब्लूडी जल्द शुरू करेगी ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया

**लोक टुडे। जयपुर**

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 882.54 करोड़ रुपये की लागत से 137 सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों को वित्तीय मंजूरी दे दी है। यह बड़ा फैसला बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने और प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में निर्बाध सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण और बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। राज्य सरकार के इस फैसले से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस वित्तीय सहमति के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा इन सभी स्वीकृत सड़कों के निर्माण के लिए बेहद जल्द ही ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, ताकि मानसून और आगामी सीजन से पहले धरातल पर सिविल कार्य सुचारू रूप से शुरू किए जा सकें।

### जल्द शुरू होगी निविदा प्रक्रिया-

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इन सभी स्वीकृत कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जल्द ही ऑनलाइन निविदा (टेंडर) प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी कार्य तय गाइडलाइंस के अनुसार पूरे किए जाएं।

### बजट वादों को धरातल पर लाने का विजन

मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है कि बजट की प्रत्येक घोषणा समयबद्ध तरीके से पूरी हो और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यह वित्तीय सहमति उसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। आमतौर पर बजटीय घोषणाओं के बाद प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों में लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्पष्ट मंशा के अनुसार इस बार सभी विभागों को आपसी समन्वय और त्वरित निर्णय प्रक्रिया के साथ काम करने के कड़े निर्देश दिए गए थे। सरकार का यह प्रयास है कि बजट की प्रत्येक घोषणा केवल कागजों और फाइलों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

### विशेष निगरानी दल भी होंगे गठित

सार्वजनिक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इन 137 सड़क कार्यों की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि जिन क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति अत्यधिक जर्जर थी या जहां यातायात का दबाव बहुत अधिक बढ़ चुका था, उन्हें प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। सड़कों के इस सुदृढ़ीकरण कार्य में आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी दल भी गठित किए जाएंगे।

### इन 29 जिलों की चमकेगी किस्मत-

इस वित्तीय मंजूरी से राजस्थान के लगभग सभी संभागों के महत्वपूर्ण जिलों को कवर किया गया है। इनमें जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना-कुचामन, पाली, जालोर, ब्यावर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर और सलूम्बर।

### बुनियादी ढांचे और सुशासन पर जोर -

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भजनलाल सरकार का यह कदम दूर-दराज के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगा। सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और नए संपर्कों के निर्माण से कृषि मंडियों तक किसानों की पहुंच आसान होगी और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

## डीके शिवकुमार कर्नाटक सीएम बने, संविधान हाथ में लेकर ली शपथ

**लोक टूडे। बैंगलुरु**

डीके शिवकुमार ने बुधवार को बेंगलुरु के लोक भवन में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान वे हाथ में संविधान रखे हुए थे। शिवकुमार को 30 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया था। वे सिद्धारमैया की जगह राज्य की कमान संभालेंगे। वहीं जी परमेश्वर ने नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। शिवकुमार के अलावा 13 विधायकों ने भी शपथ ली। इनमें पूर्व सीएम सिद्धारमैया के एमएलसी बेटे यतींद्र सिद्धारमैया भी शामिल हैं। सिद्धारमैया ने 28 मई को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। सिद्धारमैया 20 मई 2023 से 28 मई 2026 तक मुख्यमंत्री रहे।

## अहमदाबाद में 166 बांग्लादेशी पकड़े गए:300 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए, शहर के तीन इलाकों में पुलिस का एक्शन

**अहमदाबाद**

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर के तीन इलाकों से 300 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जांच में 166 बांग्लादेशी पाए गए हैं, जबकि अन्य संदिग्धों के डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है।
2 जून की रात चलाए गए अभियान में अहमदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच ने चंडोला, गुलाबनगर और खोडियारनगर क्षेत्रों में कार्रवाई की थी। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को क्राइम ब्रांच कैंपस में रखा गया है।

### पूरे शहर में तलाशी अभियान

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि चंदोला इलाके में लगातार चल रहे अभियानों के कारण बड़ी संख्या में अवैध निवासी एक जगह टिकने से बच रहे हैं।

## दिल्ली की 6 मंजिला होटल में भीषण आग

# 21 की मौत

## जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग

## 17 मृतक अफ्रीकी-बांग्लादेशी

### 40 से ज्यादा लोगों को बचाया, रेस्क्यू के दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल

**लोक टुडे। नई दिल्ली**

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर (हौज रानी) इलाके में बुधवार सुबह एक छह मंजिला होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में अधिकांश विदेशी नागरिक हैं, जो इलाज के लिए भारत आए थे। दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जान बचाने के लिए कई लोग ऊपरी मंजिलों से नीचे कूद गए।

### रेस्तरां से शुरू हुई आग, पूरी इमारत बनी डब्बा -

दमकल विभाग के अनुसार सुबह करीब 8:50 बजे होटल 'फ्लॉरिश स्टे' के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित 'लेमन ग्रीन' रेस्तरां में आग लगी। देखते ही देखते आग और जहरीले धुएं ने पूरी छह मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। तंग गलियों के कारण दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ी।

### खिड़कियों से कूदे लोग, स्थानीय बने देवदूत -

होटल के कमरों में धुआं भरने के बाद फंसे हुए लोगों में चीख-पुकार मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ महिलाएं और पुरुष जान बचाने के लिए चौथी और पांचवीं मंजिल की खिड़कियों से लटकते और नीचे कूदते नजर आए। नीचे मौजूद स्थानीय निवासियों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए जमीन पर गद्दे और तिरपाल बिछा दिए, जिससे कई लोगों की जान बच गई। घायलों को तुरंत पास के मैक्स और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

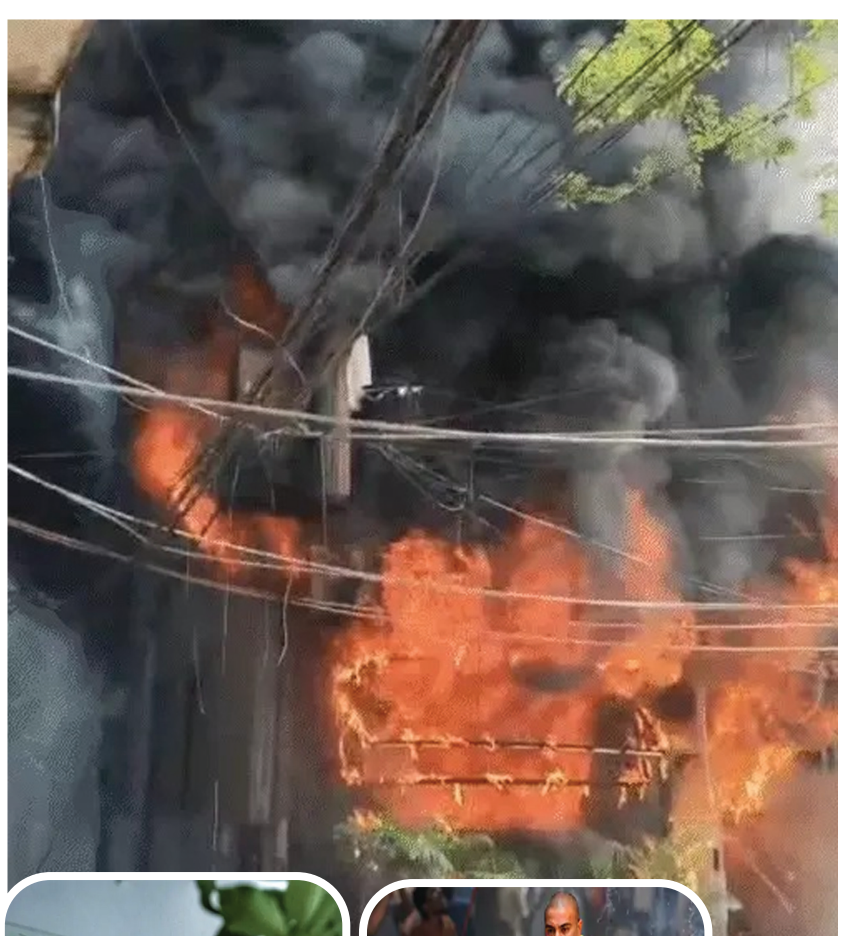

### केवल 6 कमरों की थी अनुमति, चल रहे थे 25-

अवैध संचालन: होटल को 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' योजना के तहत सिर्फ 6 कमरे चलाने का लाइसेंस था, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर 25 कमरे बनाए गए थे। एक ही निकास द्वार: पूरी छह मंजिला इमारत में आने-जाने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता था, जो आग लगने के बाद बंद हो गया। फायर एनओसी का उल्लंघन: इमारत में आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे।

### पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान -

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पुलिस ने होटल मालिक और प्रबंधन के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या (धारा 304) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान राज्यपाल हरिभाऊ बागडे व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी ने दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने से हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

### हाई कोर्ट ने जनवरी में मांगा था एक्शन प्लान, अब हादसा

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में दावा किया गया है कि राजधानी में करीब 1000 लाइसेंसी होटल और गेस्ट हाउस हैं, लेकिन केवल 52 के पास वैध फायर ह्हष्ट है। इस साल 7 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को फायर सेफ्टी पर कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया था।

## ममता की टीएमसी टूटी, 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया

### ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना, सोमवार को पार्टी से निकाले गए थे

**लोक टुडे। कोलकाता**

पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी में फूट पड़ गई है। सोमवार को पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी के 58 बागी रू ने विधायक दल का नेता घोषित किया। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंपा। जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उप नेता बनाया गया है। वहीं अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। हालांकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से इनकार किया है।

सोमवार को अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को भेजे गए पत्र में शोभनदेव को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा था। विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी ने शिकायत की थी कि इस प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। शिकायत के बाद ममता ने दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

## ट्रोलिंग से टूटी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता विश्नोई, जहरीला पदार्थ पीया, अस्पताल में भर्ती

**लोक टूडे। जोधपुर**

सोशल मीडिया की चमक-दमक के पीछे छिपे दबाव और मानसिक तनाव का एक और गंभीर मामला जोधपुर से सामने आया है। जोधपुर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई द्वारा कथित रूप से जहरीला पदार्थ सेवन करने के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका उपचार मथुरादास माथुर अस्पताल में चल रहा है।
जानकारी के अनुसार अनीता बिश्नोई हाल ही में अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में आई थीं। 'कपड़े हो गए छोटे शर्म कोनी आवे' शीर्षक से की गई उनकी पोस्ट तेजी से वायरल हो गई। पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उन्हें समर्थन के साथ-साथ तीखी आलोचनाओं और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। कई यूजर्स ने उनकी पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें लगातार रोस्ट करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर मिल रही नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से अनीता मानसिक रूप से काफी परेशान थीं। इसी बीच उन्होंने एक भावुक पोस्ट साझा की, जिसमें संकेत दिया कि वह बेहद तनाव में हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 'अब आपकी बहन आपके साथ नहीं रहेगी।' इसके कुछ समय बाद उनके जहरीला पदार्थ पीने की सूचना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। उनकी स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का दौर जारी है और बड़ी संख्या में लोग उनके

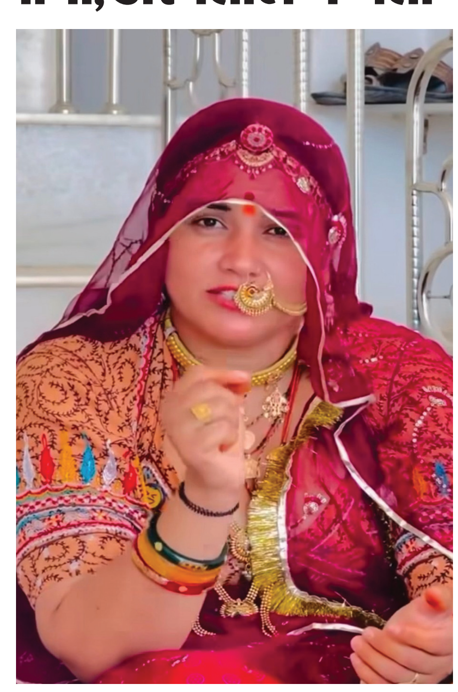

जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। यह घटना एक बार फिर सोशल मीडिया ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग के गंभीर प्रभावों को उजागर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन आलोचना और अपमानजनक टिप्पणियां कई बार लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति के साथ संवेदनशीलता और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है।

## सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

# महिला उत्पीड़न और हिंसा समाज के लिए कलंक

2013 में उषा मेहरा आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा था कि यौन उत्पीड़न तथा तमाम अपराधों की शिकार महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर की जरूरत है, जिसमें महिलाओं को इलाज के साथ-साथ दूसरी सुविधाएं भी मिल सकें। 2015 में इसी रिपोर्ट के आधार पर देशभर में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए। भारत में '181' टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर है। जैसे ही कोई परेशान महिला इस नंबर पर फोन करती है, जिस जगह से वह फोन कर रही होती है, यह नंबर अपने आप वहां के सखी वन स्टॉप सेंटर पर चला जाता है। स्क्रीन पर महिला का नाम, नंबर, जगह आदि दिखाई देने लगते हैं। इन केंद्रों पर काम करने वाली स्त्रियां, फौरन महिला से संपर्क करती हैं। यहां महिलाओं को पुलिस सहायता, आवास, खाना, इलाज, कपड़े, तथा अन्य जरूरत का सामान दिया जाता है। एक ही स्थान पर इन सभी सुविधाओं को प्रदान इसलिए किया गया है कि परेशान स्त्रियों को अलग-अलग जगहों पर भटकना न पड़े। यहां जिस तरह की महिलाएं आती हैं, उनकी कहानी सुनकर दिल दहल उठता है। इनमें से बहुत-सी महिलाएं पढ़ी-लिखी हैं, आत्मनिर्भर भी हैं। कई विदेश में रहकर भी तरह-तरह की हिंसा और अपराध झेलने के लिए मजबूर होती हैं। किसी के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। किसी की हड्डी टूटी हुई है। मारपीट, घर से निकालना आम बात है। किसी को घर में खाना तो क्या, चाय और बिस्कुट खाने तक पर पाबंदी है, क्योंकि इन पर पैसे खर्च होते हैं। ये भिन्न-भिन्न आर्थिक स्थितियों से आती हैं, पर सबकी कहानी लगभग एक जैसी ही है। पति और सुसराल वालों की मारपीट, तरह-तरह की हिंसा, ब्लैकमेलिंग, या फिर यौन उत्पीड़न। ये जैसे समवेत स्वर में कहती हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि मारपीट सहकर, भूखी रहकर भी अपने संबंधों को बचा लिया जाए, पर जब बहुत मजबूर हुईं, तभी हेल्पलाइन पर फोन किया। ऐसा क्यों है कि हर तरह के अपराध झेलने के बाद भी लांछन और बदनामी सिर्फ महिलाओं के सिर ही आती है। जिन्होंने अपराध किए, उनका अक्सर कुछ नहीं बिगड़ता। महिलाओं को ही घर से बाहर निकाला जाता है। जो घरवाले दिखावे के नाम पर लड़कियों की शादी में अनाप-शनाप पैसा खर्च करते हैं, वे क्यों नहीं उनके लिए सबसे पहले एक छत का इंतजाम करते, जिससे कि किसी आपदा के समय वे वहां रह सकें। लेकिन, उन गरीब स्त्रियों का क्या, जिनके माता-पिता के पास संसाधन नहीं, वे जैसे-तैसे लड़की का विवाह करते हैं, और विवाह के बाद अक्सर मान लिया जाता है कि अब लड़की के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई। यह कथन कि 'जिस घर में डोली आई थी, वहां से अर्थी ही निकले', आज भी घरवालों के कानों में शायद गूंजता है, तभी तो, यदि लड़कियां अपने प्रति होते अत्याचारों को बताएं भी, तब भी घरवाले ध्यान नहीं देते। कहते हैं कि ऐसा तो होता ही है। एडजस्ट कर लो। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर, क्या ऐसा होता है। कितनी ही स्त्रियों को बिना आर्थिक मदद के बाल-बच्चों समेत, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वे दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होती हैं। अपने परिवार से भी शायद ही कोई सहायता मिलती है। महानगरों या नगरों में तो वन स्टॉप सेंटर मिल भी जाएंगे, लेकिन दूर-दराज के इलाकों में रहने वाली स्त्रियां आखिर क्या करें? जिन्हें अपना माना, वे ही अगर दैत्य सरीखा व्यवहार करें, तो उनसे कैसे बचें। क्योंकि यौन अपराध के बानवे प्रतिशत मामले उन्हीं के द्वारा होते हैं, जिन्हें परिवार, परिचित या मित्र कहा जाता है। हाल ही के एनसीआरबी आंकड़े बताते हैं कि अपने देश में हर साल 4.5 लाख महिलाएं तरह-तरह के अपराधों का शिकार होती हैं। इनमें 31 प्रतिशत अपराध, पति या उसके परिवारजनों द्वारा किए जाते हैं इसलिए, इन महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि जब भी जरूरत पड़े, वे मदद ले सकें। स्कूल-कालेजों में भी इनकी जानकारी दी जाए, जिससे बच्चियां और बच्चे इन नंबरों के बारे में जान सकें और सुरक्षित रह सकें।

> इन दिनों भोपाल की त्विषा शर्मा, नोएडा की दीपिका नागर और जयपुर में हुई एक अन्य ऐसी घटना काफी चर्चा में रही हैं। इन लड़कियों ने जान गंवा दी है। यदि इनके परिवार वालों ने इनकी सुनी होती, किसी हेल्पलाइन तक ये पहुंच सकतीं, तो शायद आज जीवित होतीं।

# अविश्वास से घिरती जा रहीं परीक्षाएं

**जगमोहन सिंह राजपूत**

देश में प्रश्नपत्रों का परीक्षा से पहले 'आउट' हो जाना लगभग सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। इसका विस्तार बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षाओं तक फैल चुका है। सरकारी तंत्र ने अगले वर्ष के लिए सुधारों का आश्वासन दिया है। यह आवश्यक भी था, लेकिन जो अविश्वास पूरे देश में फैल चुका है, क्या उसका समाधान भी हो पाया है? अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। कुछ लोग तो वर्षों से इस प्रकार के अवैध कार्यों को व्यवसाय की तरह संचालित करते रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें कहीं न कहीं से संरक्षण भी मिलता रहा होगा। हर बार सरकारी तंत्र प्रश्नपत्र तैयार करने, उसे परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने और परीक्षा प्रारंभ होने तक उसकी गोपनीयता बनाए रखने की व्यवस्था में सुधार करता है, लेकिन समस्या का एक बड़ा पक्ष ऐसा भी है, जिसे सभी जानते हैं, पर उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ वर्ष पहले बिहार की एक बोर्ड परीक्षा के परिणामों को लेकर देशव्यापी चर्चा हुई थी। उस दौरान एक छात्रा का यह कथन व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करने वाला था कि मैं तो सेकेंड डिवीजन में पास होना चाहती थी, चाचा ने टाप करा दिया। यह एक ऐसा संकेत था, जो समस्या के वास्तविक समाधान की दिशा दिखा सकता था। हमें इस पर भी विचार करना होगा कि आखिर लीक हुए प्रश्नपत्र कौन खरीदता है? इसके लिए धन तो परिवार ही देता है और साल्वर, वह भी नीट जैसी परीक्षा में, कौन बन सकता है? कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा छात्र या डाक्टर बन चुका सुशिक्षित व्यक्ति ही यह कार्य कर सकता है। क्या इस देश ने कभी नागरिकों को यह बताया कि किसी साल्वर को या बड़ी धनराशि देकर अपने लाड़लों के लिए प्रश्नपत्र खरीदने वाले परिवार के किसी सदस्य को क्या सजा मिली? इस प्रकार के मामलों और ऐसी अन्य कारगुजारियों में अपराधियों को दंडित करने के मामले में भारत इतना कमजोर क्यों है? या यूं कहें कि व्यवस्था इतनी शिथिल क्यों है? संविधान में मूलभूत कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यदि सरकार, शिक्षित वर्ग और समाज इनका पालन करते होते तो क्या प्रश्नपत्र लीक होते? आगे क्या केवल कानून बदलकर प्रश्नपत्र लीक को रोका जा सकेगा? व्यवस्था को लगातार सतर्क तो रहना ही होगा, लेकिन जब तक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मानवीय तत्व को जागृत करने में असमर्थ रहेगी, तब तक ऐसी आशंकाएं साकार होती रहेंगी और परीक्षाओं की साख पुन: स्थापित नहीं हो पाएगी। नीट के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच तेजी से चल रही है। यह स्पष्ट हो गया है कि जो लोग प्रश्नपत्र बनाने योग्य समझे गए थे, जो विशेषज्ञ माने जाते थे, वे अपेक्षित नैतिक स्तर पर खरे नहीं उतरे।

स्वतंत्रता के बाद के पहले कई दशकों तक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक क्यों नहीं होते थे। वर्ष 1965-70 तक समाज में हर तरफ ऐसे लोग उपस्थित थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग किया था, तपस्या की थी और अपना सर्वश्रेष्ठ देश तथा उसके नागरिकों के लिए समर्पित कर दिया था। आज स्थिति कहां पहुंच गई है? सत्ता में पहुंचकर या व्यवस्था का अंग बनकर सामान्य जन को भूल जाना लगभग पूरी तरह स्वीकार्य हो चुका है। महात्मा गांधी का एक सूत्र-वाक्य लगभग हर विचार-विमर्श में दोहराया जाता है कि %प्रकृति के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति के लिए नहीं। क्या नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने जैसी अनेक कष्टदायक घटनाओं के कारण इसी विचार में कहीं छिपे नहीं हैं? अंतत: वह धन-लोलुपता ही है, जो एक अनुभवी अध्यापक को अपनी नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठा को भुलाकर एक जघन्य सामाजिक अपराध की ओर धकेल देती है। यह उस शिक्षा-व्यवस्था और पाठ्यक्रम की भी असफलता है, जो विद्यार्थियों को परीक्षाएं तो उत्तीर्ण करा देता है, लेकिन शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य-नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ व्यक्तित्व-निर्माण में पूरी तरह असफल सिद्ध होता है। नैतिकता का ह्रास भारत के भविष्य पर सीधी चोट कर रहा है। विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, एआइ और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के युवा किसी से पीछे नहीं हैं। फिर भी प्रश्न यह है कि हम परीक्षाओं को ईमानदारी और विश्वास के साथ संपन्न कराने में स्वयं को असमर्थ क्यों पाते हैं? एक महत्वपूर्ण पक्ष, जिस पर अपेक्षित चर्चा नहीं होती, वह है मनुष्य की बढ़ती स्वार्थपरकता, संग्रह की प्रवृत्ति और धन के निर्बाध दुरुपयोग का अहंकार। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक इस विषय पर गंभीर वैचारिक मंथन की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा-पद्धति और विकल्पों की तलाश करनी होगी, जो केवल ज्ञान और कौशल ही नहीं, बल्कि नैतिकता से संपन्न व्यक्तित्व का भी निर्माण करें। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी अपने जीवन के लक्ष्यों, सामाजिक दायित्वों और जनहित की समझ पर निरंतर आत्ममंथन करते रहना होगा। केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति पर्याप्त नहीं है। यदि उसके साथ नैतिक विकास नहीं जुड़ा होगा तो समाज और राष्ट्र दोनों ही गंभीर चुनौतियों का सामना करते रहेंगे।

> केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति पर्याप्त नहीं है। यदि उसके साथ नैतिक विकास नहीं जुड़ा होगा तो समाज और राष्ट्र दोनों ही गंभीर चुनौतियों का सामना करते रहेंगे।

# आभासी कैदखाने से बाहर निकलिए

**सिनेमा** के परदे पर अलग-अलग भूमिकाओं में कमाल की प्रतिभा दिखाने वाली मशहूर अभिनेत्री तापसी पन्नू का एक ताजा बयान खासतौर से युवा पीढ़ी और सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए।

वे चेतावनी दे रही हैं कि- ''बनावटी रूप से सुंदर दिखने और इंस्टाग्राम परफेक्ट तस्वीरों के लिए अपने शरीर पर अत्याचार करना बंद कीजिए। पन्नू के बयान की लाइन से मेल खाता हुआ एक और बयान पिछले दिनों आया था जिसमें बीते जमाने की शानदार अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि कहती हैं- ''आज कई कलाकार वास्तविक काम के बजाय केवल सतही प्रचार और दृश्यता के सहारे लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं।' ये दोनों बातें केवल फिल्मी दुनिया तक सीमित नहीं हैं। यदि गहराई से देखें तो ये हमारे समय के एक बड़े सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकट की ओर संकेत करती हैं। ये बयान उस बहुआयामी अदृश्य कारागार को उजागर करते हैं, जिसमें आज की युवा पीढ़ी स्वेच्छा से कैद हो चुकी है। एक ऐसी संस्कृति, जहां व्यक्ति की वास्तविक पहचान, प्रतिभा और व्यक्तित्व से अधिक महत्व उसकी डिजिटल पैकेजिंग और बाहरी प्रदर्शन को मिलने लगा है।

### फ्लैट मिडरिफ की सनक और वास्तविकता

फैशन, फिटनेस उद्योग और सोशल मीडिया जगत में नाभि और कमर के आसपास के हिस्से को बिल्कुल समतल, बिना किसी उभार के दिखाने को फ्लैट मिडरिफ, परफेक्ट टमी या जीरो बेली कहा जाता है। तापसी पन्नू ने खुलकर स्वीकार किया कि इस आदर्श छवि को पाने के लिए उन्होंने खुद को शारीरिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित किया और घंटों जिम में बिताए। जबकि पोषण विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों के अनुसार, महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में थोड़ा उभार होना न केवल सामान्य है, बल्कि उनके जैविक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। यह हल्का उभार केवल फैट का जमा होना नहीं बल्कि नाजुक अंगों की सुरक्षा के लिए प्रकृति द्वारा बनाया गया एक सुरक्षा कवच है। जब युवा अत्यधिक व्यायाम या कम कैलोरी वाले खान-पान से इसे जबरन हटाने का प्रयास करते हैं, तो एक तरह से प्रकृति के विरुद्ध जाकर खुद के ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।

> आज की पीढ़ी स्वस्थ दिखने की अंधी दौड़ में अपना वास्तविक स्वास्थ्य ही खोती जा रही है। और उनकी इस सनक ने दुनिया में अरबों खरबों रुपये का कारोबार खड़ा कर दिया है।

### सुंदरता का नया कारागार

विडंबना यह है कि आज की पीढ़ी स्वस्थ दिखने की अंधी दौड़ में अपना वास्तविक स्वास्थ्य ही खोती जा रही है। और उनकी इस सनक ने दुनिया में अरबों खरबों रुपये का कारोबार खडा कर दिया है। वैश्विक स्तर पर %ब्यूटी एंड वेलनेस% का बाजार आज 600 अरब डॉलर से भी अधिक का हो चुका है। कॉस्मेटिक सर्जरी, स्किन ट्रीटमेंट, वजन घटाने वाले कृत्रिम उत्पाद, एआई-आधारित फिल्टर और फिटनेस ऐप्स का यह विशाल साम्राज्य केवल उत्पाद नहीं बेच रहा, बल्कि यह असुरक्षा की भावना बेच रहा है। बाजार ने एक नया दबाव निर्मित किया है- हर समय अच्छा दिखो और दुनिया को दिखाते रहो कि तुम अच्छे दिख रहे हो। पहले सौंदर्य प्रसाधनों का उद्देश्य त्वचा को साफ और स्वस्थ रखना होता था। लेकिन आज, कैमरे के लिए शरीर को जबरन एक खास सांचे में ढाला जा रहा है। पहले कपड़े शरीर के लिए बनते थे, अब शरीर को कपड़ों के हिसाब से बदला जा रहा है। यह केवल कॉस्मेटिक बदलाव नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त जैविक संरचना के खिलाफ एक अवांछित संघर्ष है।

### तुलना का लोकतंत्रीकरण और 'कम्पैरिजन फटीग'

मनोविज्ञान में %स्थष्द्वड्डद्य ष्टश्द्वश्चड्डह्द्धह्यश्ठ्ठ ञ्चह्ड्डश्च% यह बताता है कि मनुष्य अपने मूल्यांकन के लिए दूसरों से तुलना करता है। पूर्व की पीढ़ियों में यह तुलना मोहल्ले, स्कूल या दफ्तर के सीमित दायरे तक होती थी। परंतु आज, सोशल मीडिया ने तुलना का वैश्वीकरण या लोकतंत्रीकरण कर दिया है। एक किशोर सुबह उठते ही इंस्टाग्राम पर लॉस एंजेलिस के मॉडल, सियोल के के-पॉप स्टार और मुंबई के इन्फ्लुएंसर्स या बॉलीवुड स्टार्स को एक साथ देखता है। लेकिन वह जिस 'सौंदर्य' को देखता है, वह दरअसल फिल्टर, फोटो एडिटिंग, एआई रीटचिंग और विशेष प्रकाश व्यवस्था का परिणाम होती है। इस छद्म जाल को दर्शक परम सत्य मान लेता है। लगातार ऐसे, कभी हासिल न किए जा सकने वाले मानकों से तुलना करते रहने के कारण, युवाओं का मस्तिष्क तुलना की थकान का शिकार हो जाता है, जो अंतत: आत्म-अस्वीकृति और गहरे अवसाद में बदल जाता है।

### नई पीढ़ी का संकट: जब प्रतिभा हार मान ले

इस आत्म-अस्वीकृति के भाव से ही इस विषय का सबसे डरावना और संवेदनशील पहलू शुरू होता है, जो युवा मनोविज्ञान और अवसाद के गहरे कारणों की ओर इशारा करता है। कुछ वर्ष पहले पत्रकारिता के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान मुझे एक ही ऐसा अनुभव हुआ था जिसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। टेलीविजन पत्रकारिता और एंकरिंग के व्यावहारिक पक्षों पर बातचीत चल रही थी, तभी एक होनहार छात्रा ने बेहद सहज लेकिन गहरे दर्द के साथ कहा-सर, टीवी एंकर के लिए मेरा सिलेक्शन तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा रंग काला है और मैं सुंदर भी नहीं हूँ। एक पल के लिए तो इस कथन पर सन्नाटा छा गया। कुछ सूझा ही नहीं कि उस छात्रा को क्या जवाब दिया जाए। उस छात्रा ने अपनी भाषा, ज्ञान, अभिव्यक्ति, क्षमता या मेहनत के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी त्वचा के रंग के आधार पर अपने भविष्य का फैसला पहले ही कर लिया था। वह अपनी योग्यता साबित करने की दौड़ में उतरने से पहले ही मानसिक रूप से हार मान चुकी थी। यह केवल एक छात्रा की कहानी नहीं है। यह नई पीढ़ी की उस मूक विवशता और अंतर्द्वंद्व की अभिव्यक्ति है, जो विज्ञापन उद्योग, मनोरंजन जगत और सोशल मीडिया के रूढ़ सौंदर्य मानकों के कारण उनके अवसाद का कारण बन रही है।

# ऐसा ज्ञान बेकार है जो करुणा न जगाए, संवेदनशील बनें

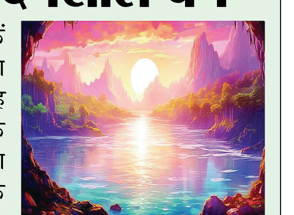

मनुष्य चाहे कितनी ही पुस्तकें पढ़ ले, उसके जाने के बाद लोग उसके शब्दों को नहीं, बल्कि यह याद रखते हैं कि उसने कितनों के आंसू पोंछे, कितनों को सहारा दिया और कितनों के लिए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई।

जीवन का मूल्य इस बात में नहीं कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया है, बल्कि इस बात में है कि हमारे कारण कितने लोगों का दुख कम हुआ। मनुष्य इस संसार में जन्म केवल अपने लिए नहीं लेता। अगर उसका समस्त ज्ञान, सारी विद्वता और उपलब्धियां केवल उसके अहंकार की दीवारें ऊंची करने में लग जाएं, तो वह ज्ञान नहीं, सिर्फ बोझ है। मैं उस विद्या को अधूरी मानता हूं, जो मनुष्य के भीतर करुणा न जगाए। मैंने अपने जीवन में देखा है कि समाज विद्वानों का तो सम्मान करता है, मगर दुखियों की पीड़ा सुनने से बचता है। लोग शास्त्रों के पन्ने तो उलटते हैं, किंतु मनुष्य के हृदय को पढ़ने का प्रयास नहीं करते। मुझे सदैव यह लगा कि यदि शिक्षा हमें मनुष्य के दुख के प्रति संवेदनशील नहीं बनाती, तो वह केवल शब्दों का संग्रह है, प्रकाश नहीं। जब मैं छोटा था, तब मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा। मैंने उन रातों को जिया है, जब दीपक जलाने के लिए हमारे यहां तेल भी नहीं हुआ करता था और सड़क की मद्धिम रोशनी में पढ़ना पड़ता था। उस समय मैंने जाना कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य क्या है। समाज में मैंने अनेक लोगों को देखा, जो धर्म और परंपरा की बड़ी-बड़ी बातें तो करते थे, किंतु एक विधवा के आंसू उन्हें विचलित नहीं करते थे। वे शास्त्रों की रक्षा में इतने व्यस्त हो गए थे कि मनुष्यता की रक्षा करना तक भूल गए। तब मेरे भीतर यह प्रश्न बार-बार उठता था कि अगर किसी व्यवस्था के कारण मनुष्य का जीवन अपमान और पीड़ा में डूब जाए, तो उस व्यवस्था की पवित्रता का क्या अर्थ रह जाता है? धर्म वह नहीं हो सकता, जो करुणा को कुचल दे। मनुष्य का कर्तव्य केवल सत्य को जानना नहीं, बल्कि अन्याय के सामने खड़े होने का साहस रखना भी है। मेरे लिए जीवन का उद्देश्य पीड़ित मनुष्य की पीड़ा को थोड़ा कम कर देना है। यदि आपके कारण किसी निराश व्यक्ति को आशा मिले, किसी भूखे को भोजन मिले, अशिक्षित को शिक्षा मिले, अपमानित को सम्मान मिले, तो समझिए आपका जीवन सार्थक हुआ। सच्चा ज्ञान वही है, जो सिखाए कि हर मनुष्य का दुख हमारे अपने दुख से अलग नहीं है। हम सब एक-दूसरे से जुड़े हैं। मनुष्य चाहे कितनी ही पुस्तकें पढ़ ले, उसके जाने के बाद लोग उसके शब्दों को नहीं, उसके व्यवहार को याद रखते हैं। वे यह याद रखते हैं कि उसने कितनों के आंसू पोंछे, कितनों को सहारा दिया और कितनों के लिए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। जीवन की सार्थकता ज्ञान के संचय में नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को दूर करने में है। सच्चा मनुष्य वही है, जो शास्त्रों के पन्ने पलटने के बजाय इन्सानी दिल को पढ़े और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखे। सदैव प्रतिष्ठा से ऊपर मानवता और सेवा को चुनें। आपके जाने के बाद लोग आपकी उपलब्धियों को नहीं, बल्कि आपकी संवेदनशीलता को याद रखेंगे।

# पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए जरूरी है खेत बचाओ अभियान

> इस वर्ष यह खर्च कहीं अधिक बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि अधिकतर उर्वरकों का आयात किया जाता है और अमेरिका-ईरान तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं।

यह अच्छा है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति में कठिनाई और उनके मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने खेत बचाओ अभियान शुरू किया। इस अभियान को शुरू करने के पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों, आइसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों और किसान संगठनों से गहन संवाद किया, उससे यह पता चलता है कि वे इस अभियान को वास्तव में सफल होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे किसी अभियान की सफलता जन भागीदारी और जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। नि:संदेह इस अभियान में केंद्र सरकार को राज्यों का सक्रिय सहयोग चाहिए होगा।

इसी तरह यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि आम किसान यह समझें कि रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग केवल खेती की लागत ही नहीं बढ़ाता, बल्कि खेतों की मिट्टी की उर्वर क्षमता को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त भूजल भी दूषित होता है। एक ऐसे समय जब जलवायु बदल रही है, तब उर्वरकों का अंसतुलित उपयोग खेती के सामने गंभीर चुनौती बन रहा है। समस्या यह है कि औसत किसान यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल अंतत: उनके लिए घाटे का सौदा ही सिद्ध होता है, क्योंकि प्रारंभ में तो फसल अच्छी होती है, लेकिन समय के साथ खेतों की मिट्टी दूषित हो जाने के कारण उपज प्रभावित होती है। वैसे तो प्रधानमंत्री ऐसी अपील करते रहे हैं कि किसान रासायनिक उर्वरकों का सही उपयोग करने के लिए खेतों की मिट्टी का परीक्षण कराएं और जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दें, लेकिन इसके बाद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए और रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग जारी है। इसका एक कारण उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी है। एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी पर खर्च किए। इस वर्ष यह खर्च कहीं अधिक बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि अधिकतर उर्वरकों का आयात किया जाता है और अमेरिका-ईरान तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा की मानें तो जहां दो बोरी उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता होती है, वहां किसान चार बोरी का उपयोग करते हैं। वास्तव में जब भी कोई वस्तु सब्सिडी के चलते कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है तो उसका अनावश्यक उपयोग बढ़ जाता है। तथ्य यह भी है कि किसानों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने वाले उर्वरक की कालाबाजारी भी होती है, क्योंकि उसका इस्तेमाल औद्योगिक रसायन के रूप में भी होता है।

# पृथ्वी का भविष्य तय करेंगे अगले पांच वर्ष, मानवीय प्रयास के बाद स्थिति चिंताजनक

**कार्बन** उत्सर्जन को कम करने में मानवीय प्रयास कुछ हद तक सफल रहे हैं और इसकी रफ्तार धीमी भी हुई है। फिर भी स्थिति चिंताजनक है। चरम गर्मी, समुद्र स्तर में वृद्धि जैसी घटनाएं आम हो रही हैं। भविष्य तय नहीं है। वैज्ञानिक कई संभावित जलवायु परिदृश्य तैयार कर रहे हैं। 'आरसीपी 8.5' को हटाना प्रगति का संकेत है। हमने सबसे खराब संभावित स्थिति से बचाव तो कर लिया है, लेकिन सबसे अच्छे भविष्य को अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं।

जलवायु परिवर्तन से जुड़े नए परिदृश्य जब भी जारी किए जाते हैं, तो उनमें हमेशा एक गहरी दिलचस्पी होती है। ये परिदृश्य बताते हैं कि भविष्य में मौसम कैसा होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उत्सर्जन कम करने के लिए कितनी तेजी से कदम उठाते हैं। हाल ही में, घोषित सात नए परिदृश्यों में एक उच्च उत्सर्जन वाला परिदृश्य 'आरसीपी 8.5' व उसका उत्तराधिकारी 'एसएसपी 5-8.5', अब हटा दिया गया है। इन परिदृश्यों में माना गया था कि वर्ष 2100 तक पृथ्वी का तापमान औद्योगिक काल से पहले की तुलना में लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता था। वैज्ञानिकों ने इस परिदृश्य को इसलिए हटाया, क्योंकि दुनिया में जलवायु कार्रवाई का असर दिखने लगा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत वाहन व बैटरी तकनीक के विस्तार ने उत्सर्जन वृद्धि की रफ्तार को धीमा किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वैज्ञानिक भविष्यवाणियां गलत थीं, बल्कि मानव प्रयास कुछ हद तक सफल रहे हैं। फिर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वैश्विक उत्सर्जन अब भी रिकॉर्ड स्तर पर है। लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के बाद ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। चरम गर्मी, बाढ़, सूखा व समुद्र स्तर में वृद्धि जैसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। भविष्य तय नहीं है। इसलिए, वैज्ञानिक कई संभावित जलवायु परिदृश्य तैयार करते हैं। ये परिदृश्य ऊर्जा उपयोग व वैश्विक नीतियों में संभावित बदलावों के आधार पर बनाए जाते हैं। वैज्ञानिक इनका अध्ययन अलग-अलग जलवायु मॉडलों के माध्यम से करते हैं, ताकि भविष्य के प्रभावों का ज्यादा सटीक अनुमान लगाया जा सके।पहले यह उम्मीद थी कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है, लेकिन अब सबसे बेहतर संभावना में भी तापमान लगभग 1.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

## भारत-बांग्लादेश सीमा पर तनाव, कथित अवैध नागरिकों को लेकर बीएसएफ और बीजीबी आमने-सामने

ढाका (एजेंसी)। भारत-बांग्लादेश सीमा पर कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर एक असामान्य स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के बीच कई दौर की बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल सीमा क्षेत्र में कुछ लोगों को लेकर दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच गतिरोध की स्थिति बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी 24 परगना जिले के पेट्रापोल क्षेत्र स्थित जयंतिपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के पास कुछ कथित बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा के निकट नो-मैन्स लैंड क्षेत्र में देखा गया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए गए। इसके बाद बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसी बीजीबी ने मामले पर आपत्ति जाहिर की और संबंधित व्यक्तियों की नागरिकता तथा पहचान के सत्यापन की मांग की। बताया गया कि इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग आयोजित की गई। हालांकि प्रारंभिक बातचीत में कोई स्पष्ट समाधान नहीं निकल सका और मामला कुछ समय तक लंबित रहा। बीजीबी अधिकारियों का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने से पहले उसकी नागरिकता, पते और अन्य दस्तावेजों का उचित सत्यापन आवश्यक है। मामले के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई। बीजीबी ने अपनी ओर निगरानी तेज कर दी, जबकि बीएसएफ ने भी सीमावर्ती इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ाई। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों पक्षों ने सीमा पर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए हैं। यह घटनाक्रम तब आया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध प्रवासन, सीमा प्रबंधन और नागरिकता सत्यापन जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को वापस भेजना या स्वीकार करने की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत ही पूरी की जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा से जुड़े इसतरह के मामलों में दोनों देशों के बीच समन्वय और सत्यापन प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल संबंधित व्यक्तियों की पहचान और नागरिकता की पुष्टि को लेकर जांच और आधिकारिक प्रक्रिया जारी है, जबकि दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

## जापान में 5 हजार भारतीय रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर

टोक्यो(एजेंसी)। जापान में भारतीय रेस्टोरेंट उद्योग इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है। देशभर में संचालित करीब 5 हजार भारतीय रेस्टोरेंट बढ़ती लागत, सख्त नियमों और श्रमिकों की कमी के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। जापान में लगभग 69 हजार भारतीय रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ी हुई है। भारतीय और नेपाली समुदाय द्वारा संचालित ये रेस्टोरेंट जापानी शहरों में करी और मसालेदार व्यंजनों के लिए लोकप्रिय हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने विदेशी कर्मचारियों को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। पहले जहां कुशल विदेशी श्रमिकों को अपेक्षाकृत आसानी से वीजा मिल जाता था, वहीं अब स्थायी निवास और रोजगार संबंधी शर्तें सख्त हो गई हैं। इसके साथ ही रेस्टोरेंट मालिकों पर कर और प्रशासनिक खर्च का बोझ भी बढ़ा है। कई व्यवसायियों का कहना है कि कमाई घट रही है, जबकि किराया, वेतन और अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय रेस्टोरेंट उद्योग में नेपाली कर्मचारियों की भी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन नए नियमों के कारण श्रमिकों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। इससे छोटे और मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट सबसे अधिक दबाव में हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि सरकार ने राहत नहीं दी तो आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीय रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं, जिससे हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी और जापान में भारतीय खानपान की पहचान को भी झटका लग सकता है।

## पश्चिम एशिया संघर्ष में चीन द्वारा ईरान की सैन्य मदद के नहीं मिले सबूत

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हाउस एप्रोप्रियेशन्स सबकमेटी की सुनवाई में कहा कि अमेरिका को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि मौजूदा क्षेत्रीय संकट में चीन ने ईरान को सैन्य मदद दी हो। रुबियो ने बताया कि उन्होंने बीजिंग से अपील की कि वह होर्मुज स्ट्रेट में नौवहन खुलवाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करे। रुबियो ने कहा कि मैं कहूंगा कि चीन ने ईरान को किसी भी तरह की सहायता नहीं दी है और न ही उसने हमारे अभियानों या हमारी काम करने की क्षमता में कोई बाधा डाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री ने माना कि ईरान के पास चीन में बने कुछ सैन्य उपकरण हैं और दोनों देशों के बीच लंबे समय से संबंध हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हाल के संघर्ष में चीन की ओर से ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी है जिससे युद्ध की स्थिति या सैन्य संतुलन पर कोई असर पड़ा हो। रुबियो ने चीन के रवैये को सावधानीपूर्ण बताया। उनका कहना था कि बीजिंग ने ईरान के साथ अपने व्यापक रणनीतिक संबंधों के बावजूद इस संकट में सीधे तौर पर शामिल होने से बचने की कोशिश की है। साथ ही रुबियो ने चीन से संयुक्त राष्ट्र में ज्यादा रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की, खासकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले समुद्री यातायात में आ रही बाधाओं को दूर करने के प्रयासों में। रुबियो के मुताबिक अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है, जिसका उद्देश्य इस अहम समुद्री मार्ग में पैदा हुई स्थिति का समाधान करना है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। रुबियो ने कहा कि अगर वास्तव में वे जलडमरूमध्य को बंद किए जाने के खिलाफ हैं, तो उन्हें इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए या कम से कम इससे दूरी बनाते हुए वीटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिरता बहाल करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए चीन के पास मजबूत आर्थिक कारण हैं, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर काफी निर्भर है।

# रुबियो के नए दावे से पलटी थ्योरी, जीवित हैं मोजतबा खामेनेई!

**वॉशिंगटन (एजेंसी)।** वॉशिंगटन(ईएमएस)। भीषण संघर्षविराम की कोशिशों के बीच अमेरिका ने ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है, जो उसके अब तक के बयानों से बिल्कुल उलट है। अमेरिका अब तक लगातार यह कहता आया था कि मोजतबा खामेनेई अमेरिकी सैन्य हमले में मारे गए हैं या फिर वे इतने गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं कि अब सक्रिय नहीं हैं। हालांकि, अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि मोजतबा खामेनेई न सिर्फ जीवित हैं, बल्कि सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आने के बावजूद देश के प्रशासनिक और रणनीतिक फैसलों में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के सामने बोलते हुए रुबियो ने स्पष्ट किया कि ऐसे पुख्ता संकेत मिले हैं कि खामेनेई पर्दे के पीछे से लगातार देश की निर्णय प्रक्रिया में शामिल हैं और ईरान के सरकारी मामलों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए संयुक्त सैन्य हमलों के दौरान खामेनेई घायल हो गए थे, जिसके बाद से वे सार्वजनिक मंचों पर दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन का अब मानना है कि वे किसी सुरक्षित स्थान से एन्क्रिप्टेड संचार माध्यमों और अपने बेहद भरोसेमंद नेटवर्क के जरिये सरकारी कामकाज की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।

रुबियो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम को स्थायी रूप देने की कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वॉशिंगटन अब भी तेहरान के साथ किसी समझौते की संभावना देख रहा है और हालात कभी भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट शर्तों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ईरान प्रतिबंधों में राहत चाहता है, तो उसे हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना होगा और अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही पर से सभी प्रतिबंध या शुल्क हटाने होंगे। साथ ही ईरान को यह भरोसा देना होगा कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में सहयोग करेगा।

इसके अलावा, अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर दीर्घकालिक सख्त सीमाओं को स्वीकार करे या यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया था कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने को लेकर जल्द कोई समझौता हो सकता है। हालांकि, ईरान ने फिलहाल मध्यस्थों के जरिए चल रही वार्ताओं को रोक रखा है। तेहरान का कहना है कि जब तक लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई बंद नहीं होती, तब तक किसी नई बातचीत का कोई औचित्य नहीं है।

## कनाडा में भारत-पाकिस्तान से आने वाले आवेदनों की प्रोसेसिंग अवधि में हुआ सुधार

टोरंटो। कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ एंड सिटिजनशिप कनाडा ने नए आवेदनकर्ताओं के लिए प्रोसेसिंग टाइम की ताजा जानकारी दी है। पहले से तय समय से तुलना करने पर पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान से आने वाले कई आवेदनों की प्रोसेसिंग अवधि में सुधार हुआ है। वहीं, नाइजीरिया और अमेरिका से जुड़े कुछ आवेदन श्रेणियों में प्रतीक्षा अवधि बढ़ी है। वर्क परमिट आवेदनों में पाकिस्तान से आवेदन करने वालों के लिए प्रोसेसिंग टाइम 6 सप्ताह और भारत के लिए 9 सप्ताह किया गया है। कनाडा के अंदर से किए गए आवेदनों की प्रोसेसिंग 212 दिनों से घटकर 206 दिन हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया के आवेदकों को बड़ा झटका लगा है। वहां वर्क परमिट की प्रोसेसिंग अवधि 6 सप्ताह से बढ़कर 12 सप्ताह हो गई है। अमेरिका और फिलीपींस के लिए समय सीमा 5 और 8 सप्ताह है। स्टडी परमिट के मामले में भी पाकिस्तान के आवेदकों को बड़ी राहत मिली है। वहां प्रोसेसिंग टाइम 11 सप्ताह से घटकर 7 सप्ताह कर दिया गया है। भारत के लिए यह अवधि 4 सप्ताह है। कनाडा के अंदर से किए गए स्टडी परमिट आवेदनों की प्रोसेसिंग अवधि 6 सप्ताह है। वहीं, नाइजीरिया में यह समय 5 सप्ताह से बढ़कर 6 सप्ताह हो गया है। अमेरिका और फिलीपींस के लिए प्रोसेसिंग टाइम 5 सप्ताह है। विजिटर वीजा आवेदनों में ज्यादातर देशों के लिए प्रोसेसिंग टाइम में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत के लिए यह अवधि 28 दिन कर दी गई है। अमेरिका के लिए 25 और फिलीपींस के लिए 20 दिन कर दी गई है। कनाडा के अंदर से किए गए विजिटर वीजा आवेदनों का प्रोसेसिंग टाइम 11 दिनों से बढ़कर 16 दिन हो गया है। पाकिस्तान के लिए यह अवधि 50 दिनों पर स्थिर रही, जबकि नाइजीरिया में यह 47 दिनों से बढ़कर 48 दिन हो गई। सुपर वीजा श्रेणी में भारत और पाकिस्तान के आवेदकों को सबसे बड़ा फायदा मिला है। भारत के लिए प्रोसेसिंग टाइम 160 दिनों से घटकर 117 दिन कर दिया है। वहीं पाकिस्तान में यह अवधि 107 दिनों से घटकर 75 दिन कर दी है। इसके विपरीत, अमेरिका से किए गए सुपर वीजा आवेदनों की प्रोसेसिंग अवधि 103 दिनों से बढ़कर 115 दिन हो गई है। नाइजीरिया में यह समय 35 से बढ़कर 37 दिन हुआ, जबकि फिलीपींस में यह 32 दिनों पर स्थिर रहा।

## आयोवा नरसंहार- आखिर सुपरपावर अमेरिका में क्यों नहीं थम रहा खूनी खेल?

**वाशिंगटन (एजेंसी)।** अमेरिका के आयोवा राज्य का मस्कटाइन शहर मंगलवार की सुबह अंधाधुंध गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। एक ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हमलावर ने खुद को भी उड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक, यह खूनी खेल एक घरेलू विवाद का नतीजा था, जिसे 52 वर्षीय रायन विलिस मैकफारलैंड नामक शख्स ने अंजाम दिया। पार्क एवेन्यू के एक घर से शुरू हुआ मौत का यह सिलसिला मिल स्ट्रीट और ग्रैंडव्यू एवेन्यू तक जा पहुंचा। पुलिस ने जब संदिग्ध को घेरा, तो उसने खुद को गोली मार ली। पुलिस भले ही इसे घरेलू मामला बताकर पल्ला झाड़ ले कि अब समुदाय को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस भयावह घटना ने एक बार फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है आखिर अमेरिका में बार-बार मास शूटिंग क्यों हो रही है?

### हथियारों की सनक या कानून की लाचारी?

आयोवा का यह नरसंहार कोई इकलौती घटना नहीं है। यह अमेरिकी समाज में गहरे धंस चुके गन कल्चर की उस सड़ी हुई हकीकत को बयां करता है, जहां मामूली विवादों का निपटारा भी बंदूकों से किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका में हर नागरिक के पास घातक हथियार रखने का अधिकार तो है, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है? हर बड़ी घटना के बाद वहां गन कंट्रोल (हथियार नियंत्रण) पर बहस तो छिड़ती है, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। राजनीतिक नफा-नुकसान और हथियार लॉबी के दबाव के आगे अमेरिकी प्रशासन बेबस नजर आता है।

# ओबामा की जिस डील पर ट्रंप भड़के थे अब उसी को अपना रहे राष्ट्रपति

**-ईरान के साथ परमाणु समझौते पर चर्चा**

**वाशिंगटन (एजेंसी)।** अमेरिकी राजनीति में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा रहा हो, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा की उतनी तीखी आलोचना की हो, जितनी 2015 की ईरान परमाणु डील को लेकर की थी। ट्रंप ने उस समय जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब समझौता बताया था। साल 2018 में राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने इस डील से अमेरिका को बाहर निकालकर इसे अपनी सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धियों में गिनाया था। लेकिन अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि ईरान के साथ नए समझौते की कोशिशों में ट्रंप को उसी पुराने मॉडल का सहारा लेना पड़ सकता है, जिसे उन्होंने कभी पूरी दुनिया के सामने नाकाम और खतरनाक करार दिया था। यही वजह है कि अमेरिका में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है कि क्या

ट्रंप वास्तव में कोई नई और मजबूत डील बना रहे हैं या सिर्फ पुराने समझौते को ही नए पैकेज में पेश करने की कोशिश हो रही है।

दिलचस्प बात यह है कि ईरान के साथ चल रही मौजूदा बातचीत के कई बिंदु सीधे तौर पर ओबामा युग के जेसीपीओए की याद दिलाते हैं। प्रस्तावित समझौते में युद्धविराम बढ़ाने, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई वार्ता शुरू करने जैसी शर्तें शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान अगले 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन न करे और कभी परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी दे, जिसे तेहरान फिलहाल खारिज कर रहा है। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने दावा किया था कि ओबामा प्रशासन ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं और इस डील ने तेहरान को अरबों डॉलर दिए। लेकिन अमेरिका के पीछे हटने के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर दिया। जहां 2015 की डील के तहत ईरान केवल 3.67 प्रतिशत तक यूरेनियम संवर्धन कर सकता था, वहीं आज वह 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम जमा कर चुका है, जो हथियार-ग्रेड स्तर के बेहद करीब है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान वार्ता का पूरा ढांचा ओबामा युग की डील पर ही आधारित नजर आता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने की बात जोड़ी जा रही है। जानकारों के मुताबिक, ट्रंप इस बात को लेकर बेहद चिंतित होंगे कि उनकी डील की तुलना ओबामा की डील से न की जाए, क्योंकि उस समझौते को खत्म करना उनके पहले कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान थी। यदि नई डील में भी ईरान को प्रतिबंधों से राहत और जमे हुए अरबों डॉलर तक पहुंच मिलती है, तो ट्रंप के लिए अपने समर्थकों को यह समझाना मुश्किल होगा कि यह समझौता पुराने समझौते से किस तरह अलग और बेहतर है।

## रूस ने यूक्रेन पर किया हमला, 23 की मौत, 90 घायल

**- मिसाइल संकट ने बढ़ाई जेलेंस्की की चिंता**

**कीव (एजेंसी)।** रूस ने मंगलवार देर रात यूक्रेन पर हाल के महीनों का सबसे बड़ा और विनाशकारी हवाई हमला किया है। सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों अत्याधुनिक मिसाइलों से कीव सहित पूरे देश को निशाना बनाया गया। इस भीषण हमले में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूक्रेनी वायुसेना द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, रूस ने इस हमले में 656 ड्रोन और 73 मिसाइलें दागीं। हालांकि, यूक्रेनी

एयर डिफेंस सिस्टम ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद 54 ड्रोन और 33 मिसाइलें सुरक्षा कवच को भेदने में कामयाब रहीं, जिससे कई इलाकों में आवासीय इमारतें जमींदोज हो गईं। इस हमले ने यूक्रेन की सबसे बड़ी सैन्य कमजोरी को एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर कर दिया है, जो कि पैट्रियट एंटी-बैलिस्टिक मिसाइलों की भारी कमी है।

पैट्रियट सिस्टम रूस की एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सबसे अचूक माना जाता है, लेकिन यूक्रेन के पास इसकी बेहद सीमित संख्या है। राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने भी खुलकर स्वीकार किया कि मौजूदा हथियार आपूर्ति के सहारे वे इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों से तुरंत सैन्य मदद की गुहार लगाई है।

पैट्रियट मिसाइलों की इस किल्लत के पीछे मुख्य वजह अमेरिका की सीमित उत्पादन क्षमता है। अमेरिका इस प्रणाली का मुख्य उत्पादक है, लेकिन उसकी सालाना उत्पादन क्षमता अभी सिर्फ 650 मिसाइलों के आसपास ही है। इसके अलावा, ईरान के साथ हालिया संघर्ष में अमेरिका और इजरायल द्वारा इन मिसाइलों का भारी इस्तेमाल किए जाने से वैश्विक स्टॉक और कम हो गया है। साथ ही, ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अमेरिका पहले अपनी आंतरिक सुरक्षा जरूरतें पूरी कर रहा है, जिसके कारण यूक्रेन को आपूर्ति मिलने में देरी हो रही है। बदलते हालात के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस और अमेरिकी कांग्रेस को पत्र लिखा है। अब तक यूक्रेन सीधे तौर पर तैयार हथियार मांग रहा था, लेकिन अमेरिका के पास घटते स्टॉक को देखते हुए अब जेलेंस्की ने मिसाइलों का प्रोडक्शन लाइसेंस मांगा है। यह कदम यूक्रेन की बढ़ती हताशा के साथ-साथ एक बड़े प्रतीकात्मक बदलाव को भी दिखाता है, जहां कभी हथियार मांगने वाला देश अब खुद निर्माण तकनीक की मांग कर रहा है। रूस इस स्थिति का फायदा उठाकर हमले तेज कर रहा है। यदि पश्चिमी देशों ने जल्द ही बड़े पैमाने पर मदद नहीं भेजी, तो यूक्रेन के शहरों पर तबाही का खतरा और गहरा सकता है।

## कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने कर दिया हमला

**कुवैत सिटी (एजेंसी)।** अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव के कारण खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस बीच एक बड़े घटनाक्रम में ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। इस दावे के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहद संवेदनशील हो गई है और कुवैत की सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है।

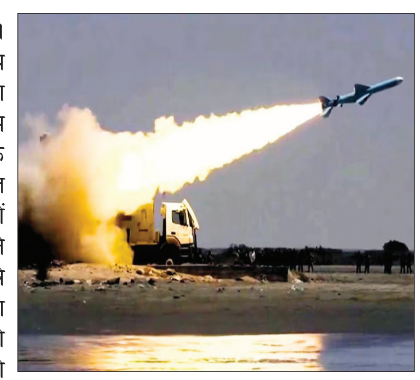

बुधवार को कुवैत के कई हिस्सों में अचानक तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देने से हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुवैत की सेना के जनरल स्टाफ ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की।

सेना ने पुष्टि की कि नागरिकों द्वारा सुनी गई धमाकों की आवाजें दरअसल उसके एयर डिफेंस सिस्टम की सक्रियता के कारण थीं। कुवैती सैन्य अधिकारियों के अनुसार, देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आसमान में ही दुश्मन की कई मिसाइलों और ड्रोनों को इंटरसेप्ट कर उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। कुवैत की सेना ने अपने बयान में कहा, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इस समय दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों का कड़ा मुकाबला कर रहा है। यदि आगे भी धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं, तो जनता पैनिक न हो, क्योंकि वे दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने के लिए की जा रही जवाबी सैन्य कार्रवाई का ही परिणाम हैं।

इस हवाई कार्रवाई के बाद कुवैती सैन्य अधिकारियों ने नागरिकों और वहां रह रहे प्रवासियों के लिए एक सख्त एडवायजरी जारी की है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वे आसमान से गिरने वाले किसी भी मलबे, छर्रों या अज्ञात वस्तुओं के पास बिल्कुल न जाएं, क्योंकि ये खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु के दिखने पर तुरंत 112 आपातकालीन हॉटलाइन पर सूचित करें। साथ ही, उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ, ईरान के सरकारी मीडिया ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और केश्म द्वीप पर अमेरिका द्वारा की गई शत्रुतापूर्ण हरकतों का सीधा बदला है। हालांकि, इन हमलों में अमेरिकी ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल कुवैत की सेना पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।

# 700 मर्दों ने किया दुष्कर्म- ब्रिटिश सांसद ने संसद में बताया पीड़िताओं का दर्द

**लंदन (एजेंसी)।** ब्रिटेन में कथित तौर पर सक्रिय रहे ग्रूमिंग गैंग और बाल यौन शोषण के मामलों को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाले और बेहद दर्दनाक खुलासे हुए हैं। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने संसद में दिए गए अपने संबोधन में कई पीड़िताओं की गवाहियों का हवाला देते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक संगठित गिरोहों ने नाबालिग लड़कियों का बेरहमी से यौन शोषण किया और इस पूरी अवधि के दौरान प्रशासनिक व संस्थागत स्तर पर भी गंभीर लापरवाहियां और विफलताएं देखने को मिलीं।

सांसद रूपर्ट लोव ने संसद के सामने इन मामलों को रखते हुए कहा कि एक स्वतंत्र जांच के दौरान जो गवाहियां सामने आईं, वे इतनी भयावह थीं कि उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने लाना बेहद जरूरी था। उन्होंने संसद से पूरी ईमानदारी के साथ अपील की कि इन बहादुर पीड़िताओं की आवाज को अनसुना न किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सरकार की पूर्व जांच रिपोर्टों और इन गवाहियों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाने वाले इन आपराधिक गिरोहों में मुख्य रूप से पाकिस्तानी मूल के कुछ टैक्सी ड्राइवर और दुकानदार शामिल थे। संसद में पेश की गई इन गवाहियों में गंभीर यौन शोषण, बेहद कम उम्र में जबरन प्रेगनेंसी, डराने-धमकाने और स्थानीय पुलिस के कथित दुर्व्यवहार का जिक्र किया गया है। लोव ने कहा कि दुनिया को वह सब सुनना चाहिए जो स्वतंत्र रेप गैंग जांच की दो हफ्तों की सुनवाई के दौरान सामने आया है।

संसद में जो गवाहियां रखी गईं, उनमें से एक पीड़िता ने अपनी दर्दनाक आपबीती बताते हुए कहा कि जब वह महज 12-13 साल की थी, तब उसके साथ अमानवीय तरीके से जबरदस्ती की गई। वहीं, एक अन्य पीड़िता की गवाही के अनुसार, आरोपियों द्वारा नस्लवादी टिप्पणियां भी की जाती थीं। एक अन्य दिल दहला देने वाले बयान में पीड़िता ने दावा किया कि जब वह 13 साल की थी, तब से लेकर अगले तीन सालों के दौरान सैकड़ों अलग-अलग पुरुषों ने उसका यौन उत्पीड़न किया। एक अन्य पीड़ित ने बताया कि बंधक बनाकर रखी गई लड़कियों को अमानवीय स्थितियों में पिंजरों तक में बंद करके रखा जाता था।

इस पूरे ग्रूमिंग गैंग पैटर्न की बात करें तो वर्ष 2025 में रूपर्ट लोव के नेतृत्व में हुई एक निजी जांच के दौरान पूरे यूके के कम से कम 85 इलाकों में इस तरह के गैंग आधारित बाल यौन शोषण की पहचान की गई थी। जांच रिपोर्टों के मुताबिक, इस नेटवर्क में एक खास पैटर्न और सरकारी संस्थाओं की घोर लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। ब्रिटेन में इस तरह के ग्रूमिंग गैंग्स का इतिहास पुराना रहा है। सबसे पहले 2002 में वेस्ट यॉर्कशायर के कीथली क्षेत्र से ऐसी चेतावनी सामने आई थी। इसके बाद साल 2010 में साउथ यॉर्कशायर के रॉदरहैम में कम उम्र की लड़कियों के साथ हुए अपराधों के मामले में एक समूह को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद इस पूरे संगठित नेटवर्क और इसके तौर-तरीकों का देशव्यापी खुलासा हुआ था।

# पुराना ढांचा बनाम नया चेहरा : राजस्थान कांग्रेस में छिड़ा 'साइलेंट वॉर' !

## मानेसर से लेकर 2023 की हार तक... क्या आलाकमान इस बार पायलट के नाम पर खेलेगा सबसे बड़ा जुआ? या सामूहिक नेतृत्व को ही मिलेगी प्राथमिकता

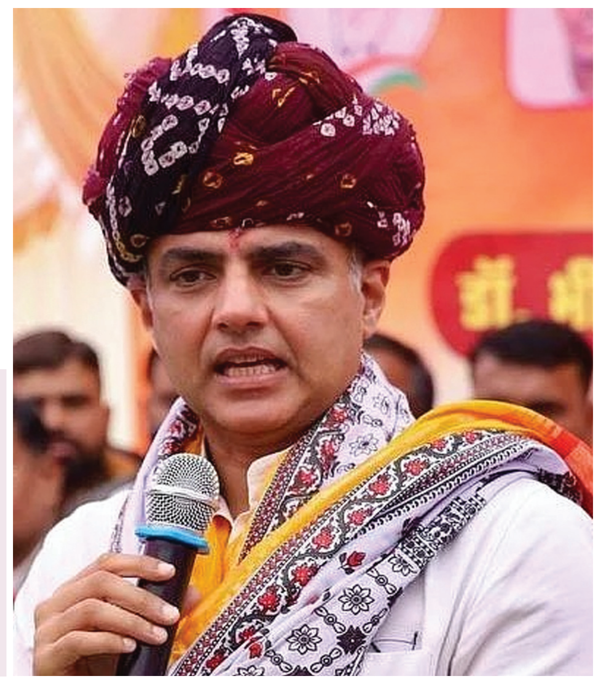

भारती जैन। जयपुर

राजस्थान की राजनीति में एक सवाल धीरे-धीरे सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य बनता जा रहा है। क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी ? या फिर पार्टी कोई ऐसा फॉर्मूला निकालेगी, जिसमें चेहरा कोई और होगा या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के कार्यकाल के बीच, कांग्रेस के भीतर सत्ता में वापसी की छटपटाहट और अंदरूनी समीकरणों ने इस बहस को एक बार फिर हवा दे दी है। राजनीति में सिर्फ वही नेता ताकतवर नहीं होता जो सामने दिखता है। कई बार असली ताकत उस नेता के पास होती है जो चेहरे तय करता है। राजस्थान कांग्रेस की अगली पीढ़ी की राजनीति को लेकर यही सबसे बड़ी बहस है। एक तरफ सचिन पायलट हैं, जो पिछले दो दशकों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का वो पुराना ढांचा है, जिसने हमेशा सामूहिक नेतृत्व और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी है। ऐसे में सवाल केवल यह नहीं है कि पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस उन्हें सीधे चेहरा नहीं बनाती, तो क्या पार्टी उनकी पसंद के किसी नेता को आगे बढ़ा सकती है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए सचिन पायलट के पूरे राजनीतिक सफर को समझना जरूरी है।

### राजनीति नहीं वायुसेना में पायलट बनने का था सपना -

7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जन्मे सचिन पायलट का सपना राजनीति नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का था, लेकिन 11 जून 2000 को एक सड़क हादसे में पिता राजेश पायलट के निधन ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई।

### राजनीतिक विरासत की जिम्मेदारी आते ही कांग्रेस में एंट्री -

साल 2002 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और सक्रिय राजनीति में एंट्री की। शुरुआत से ही उन्होंने खुद को केवल विरासत के सहारे चलने वाले नेता के रूप में पेश नहीं किया। उन्होंने गांवों की धूल भरी पगडंडियों पर यात्राएं कीं। किसानों के बीच समय बिताया, युवाओं से संवाद किया और संगठन में अपनी जगह बनाई।

### फिर 2004 में दौसा से बने सांसद -

2004 में वे दौसा से सांसद बने और उस समय लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में शामिल हुए। बाद में केंद्र सरकार में मंत्री बने। लेकिन असली चुनौती तब आई जब कांग्रेस राजस्थान में लगातार कमजोर होती जा रही थी। 2014 में जब कांग्रेस राजस्थान में लगभग साफ हो गई थी, तब पार्टी ने प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपी। उस दौर में उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को खड़ा करने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं के बीच लगातार सक्रिय रहे और कांग्रेस को दोबारा मैदान में लाने का प्रयास किया।

### यूथ आईकॉन बने, पर कुर्सी नहीं मिली -

सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति में 'धैर्य और संघर्ष' का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। साल 2013 में जब कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब राहुल गांधी ने पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा था। युवा नेता ने 5 साल तक सड़कों पर लाठियां खाईं, पदयात्राएं कीं और युवाओं को कांग्रेस से जोड़ा। नतीजा यह हुआ कि 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौट आई। युवाओं को पूरा भरोसा था कि उनका 'यूथ आइकॉन' अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा। लेकिन, ऐन वक्त पर अनुभवी अशोक गहलोत बाजी मार ले गए और पायलट को 'डिप्टी सीएम' पद से ही संतोष करना पड़ा।

### गांधी परिवार का अटूट भरोसा -

पायलट ने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी और न ही भाजपा का दामन थामा। उनके इस कदम ने गांधी परिवार (विशेषकर राहुल और प्रियंका गांधी) का उन पर भरोसा मजबूत किया। हाईकमांड ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ह्रष्टष्ट) का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी नियुक्त किया। यह दर्शाता है कि अब वे केवल राजस्थान के क्षत्रप नहीं, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरे हैं।

### अब वक्त पायलट के साथ, परीक्षा आलाकमान की -

मानेसर कांड ने जहां सचिन पायलट की राजनीतिक परिपक्वता की अग्निपरीक्षा ली, वहीं 2023 की हार ने उन्हें यह सिखाया कि पार्टी के भीतर रहकर ही लंबी लड़ाई जीती जा सकती है। आज की तारीख में पायलट का भविष्य असुरक्षित नहीं, बल्कि 'वेटिंग मोड' में है। वे जानते हैं कि समय उनके साथ है (उम्र के लिहाज से) और कांग्रेस आलाकमान के पास हिंदी बेल्ट में उनके कद का दूसरा कोई युवा और प्रभावी विकल्प मौजूद नहीं है। पायलट का वर्तमान रुख 'एक कदम पीछे खींचकर लंबी छलांग लगाने' जैसा है। वे बिना किसी विवाद के चुपचाप अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति का मिजाज हर 5 साल में बदलने का रहा है। पायलट की नजर इसी 'एंटी-इंकम्बेंसी' (सत्ता विरोधी लहर) और युवाओं के भरोसे पर है। अब गेंद कांग्रेस हाईकमांड के पाले में है। 2028 का चुनाव सिर्फ पायलट के धैर्य की नहीं, बल्कि राहुल गांधी के 'युवा नेतृत्व' को आगे बढ़ाने के वादे की भी अग्निपरीक्षा होगा।

### 2020 का मानेसर कांड 'टर्निंग पॉइंट'-

2020 का मानेसर कांड और 2023 की चुनावी हार सचिन पायलट के राजनीतिक जीवन के दो सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट हैं, जिन्होंने उनके 'आक्रामक तेवर' को 'गंभीर धैर्य' में बदल दिया है। इन दोनों घटनाओं को करीब से देखने और झेलने के बाद पायलट का राजनीतिक भविष्य अब बेहद रणनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ नजर आ रहा है। 2020 के मानेसर कांड में जब पायलट करीब 19 विधायकों के साथ दिल्ली-मानेसर के होटलों में बैठ गए थे, तब उन पर सरकार गिराने और 'अति-महत्वाकांक्षी' होने के आरोप लगे थे। इस घटना के बाद उनसे डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया गया। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में पायलट ने अपनी छवि को पूरी तरह बदला है।

# विदुषी डॉ. धनंजया अमरावत को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय 'कवि दुलाभाया काग अवार्ड'

लोक टुडे। जयपुर

लोक साहित्य, डिंगल और चारण साहित्य की सुप्रसिद्ध विदुषी और शोधकर्ता डॉ. धनंजया अमरावत को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक अवदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्र-स्तरीय 'कवि दुलाभाया काग अवार्ड' (कवि काग पुरस्कार) से नवाजा गया है। यह सम्मान गुजरात के अमरेली जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ और कवि काग की कर्मभूमि कागधाम में आयोजित एक गरिमामय राष्ट्रीय समारोह में प्रदान किया गया। इस गौरवशाली उपलब्धि पर साहित्य जगत में हर्ष की लहर है।

उल्लेखनीय है कि कवि दुलाभाया काग पुरस्कार समिति हर साल लोक साहित्य, चारणी परंपरा और डिंगल साहित्य के संवर्धन के लिए विशिष्ट विद्वानों का चयन करती है। इस श्रृंखला में डॉ. धनंजया अमरावत का चयन राजस्थान और गुजरात के सदियों पुराने सांस्कृतिक व साहित्यिक संबंधों को और मजबूत करता है। परंपरा के अनुसार इस पुरस्कार के तहत गुजराती भाषा के लोक कलाकारों के साथ-साथ एक पुरस्कार विशेष रूप से राजस्थानी विद्वान को उनके शोध कार्य के लिए दिया जाता है, जिसके तहत डॉ. अमरावत को चुना गया। समारोह के मुख्य मंच पर डॉ. धनंजया अमरावत को सम्मान स्वरूप 51,000 की सम्मान राशि के साथ संस्थान का विशिष्ट प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न और चारणी परंपरा के प्रतीक रूप में शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया गया।

**डॉ. अमरावत का साहित्यिक योगदान-** डॉ. धनंजया अमरावत लंबे समय से चारण साहित्य, राजस्थानी डिंगल परंपरा और लोक संस्कृति के गूढ़ विषयों पर शोध कर रही हैं। उन्होंने न केवल प्राचीन पांडुलिपियों और लोक विधाओं को सहेजने का काम किया है, बल्कि अकादमिक स्तर पर भी शोध पत्रों और व्याख्यानों के माध्यम से युवा पीढ़ी को इस अनमोल विरासत से जोड़ा है। हाल ही में उन्होंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष पद का कार्यभार भी ग्रहण किया है, जो उनकी अकादमिक वरिष्ठता को दर्शाता है। डॉ. अमरावत को पूर्व में भी राजस्थानी विभागाध्यक्ष एवं महिला अध्ययन केन्द्र निदेशक का कार्यभार मिल चुका है। विभागाध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करते हुए डॉ. अमरावत ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी कि विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। अध्ययन, अध्यापन एवं शोधकार्य सुचारू रूप से पूर्ण हो। साथ ही विभाग के माध्यम से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति के विकास के लिए कार्य संपादन प्राथमिकता के साथ करने के प्रयास रहेंगे। इस मौके विश्वविद्यालय शिक्षकों, विभागीय सदस्यों एवं शोधार्थियों द्वारा नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया। इस अवसर प्रो रामसिंह आढ़ा, डॉ. विजयश्री, डॉ. गजेसिंह राजपुरोहित, डॉ. मीनाक्षी बोराण, डॉ. भरत देवड़ा, शोधार्थी विष्णुशंकर, जगदीश मगराज, माधुसिंह व शान्तिलाल उपस्थित रहे।

# तूफान से प्रभावित गांवों में पहुंची राहत, 50 राशन किट और तिरपाल बांटे

लोक टुडे। बाड़मेर

पिछले दिनों बाड़मेर जिले के सबरीनगर, तिरसिंगड़ी ओर मीठीसर गांवों में अचानक आए भीषण आंधी-तूफान ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं और बारिश के साथ आए इस तूफान में जन हानि होने के साथ ही कई परिवार प्रभावित हुए। कई परिवारों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और घरेलू सामान और पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ। गांव के कई हिस्सों में बिजली-पानी की आपूर्ति भी बाधित रही।

जिला प्रशासन के अनुरोध पर केयर्न वेदांता ऑयल एंड गैस ने सबरीनगर, तिरसिंगड़ी ओर मीठीसर गांवों के प्रभावित परिवारों के लिए 50 राशन किट और तिरपाल उपलब्ध कराए। मंगलवार को कंपनी की सीएसआर टीम की सदस्य राम्या नायर और प्रिया शर्मा सहित प्रशासन की संयुक्त टीम ने सबरीनगर गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। टीम ने घर-घर जाकर जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान सरपंच आदूराम, तहसीलदार अमीन खान, नायब तहसीलदार वीके भारद्वाज, नायब तहसीलदार बिशाला ऊर्जाराम, ग्राम विकास अधिकारी शिशपाल सिंह और पटवारी जुंझार सिंह मौजूद रहे। टीम ने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। वहीं प्रशासन की टीमों ने बुधवार को भी प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित की। स्थानीय लोगों ने राहत सामग्री मिलने पर संतोष जताया।

# मुख्यमंत्री ने ली ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक

**राजस्थान बिजली के क्षेत्र में अग्रणी बनने की ओर ,विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता में करें वृद्धि**

**किसान, उद्योग और आमजन को हो निर्बाध बिजली आपूर्ति - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा**

**राज्य सरकार के प्रयास लाए रंग, गत वर्ष मई माह में बिजली खरीद 8 प्रतिशत, इस वर्ष घटकर आई 2 प्रतिशत पर**

जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2027 तक बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए ऊर्जा विभाग विद्युत उत्पादन और प्रसारण के क्षेत्र में कुशल प्रबंधन से कार्य करे। उन्होंने कहा कि थर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड जैसे माध्यमों से किसानों, उद्योगों और आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पहचान बिजली खरीदने वाला नहीं, बल्कि बिजली बेचने वाला अग्रणी प्रदेश के रूप में ओर अधिक मजबूत हो, इसके लिए विभागीय अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी से कार्ययोजना के अनुसार काम करें। उन्होंने कहा कि विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण से जुड़े कार्यों को गति प्रदान की जाए। साथ ही, 26 जिलों में किसानों को दिन में मिल रही बिजली की सुविधा को शेष जिलों में लागू करने के प्रयासों में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में हितधारकों को पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना से लाभांवित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी डिस्कॉम विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए समन्वय से कार्य करें। साथ ही, उन्होंने जोधपुर डिस्कॉम में आरडीएसएस के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र को तकनीकी स्तर पर ओर अधिक प्रभावी बनाया जाए। बैठक में बताया गया कि उत्पादन निगम की कोयला आधारित विद्युत इकाइयों ने 02 जून को सर्वाधिक क्षमता का उपयोग कर 7 हजार 171 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया। इसी प्रकार गत वर्ष मई माह में कुल बिजली आवश्यकता की 8 प्रतिशत बिजली खरीदी गई। वहीं, ठोस एवं प्रभावी प्रयासों से समान अवधि में इस वर्ष महज 2 प्रतिशत बिजली की ही खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता में वृद्धि के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएं। इसी तरह बताया गया कि राज्य सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी के 60 जीएसएस स्थापित हो चुके हैं। वहीं, 151 जीएसएस का कार्य प्रगति पर है। साथ ही, इसी समयावधि में 33 केवी के 444 सब स्टेशन स्थापित हुए हैं तथा 211 सब स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा, ऊर्जा विभाग शासन सचिव आरती डोगरा सहित ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादकः नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)